

निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 71/अपील/21

तारीख दायरा: 20.12.2021

कालू आ० हिन्दू जाति दांगी नि० सिलोरी तहसील पिडावा (अपीलान्त)
बनाम
राजस्थान सरकार जर्जे तहसीलदार पिडावा (रेस्प०)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पिडावा निर्णय दिनांक 23.09.2021
मिसल न० 179/2021

उपस्थित:- श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार

:- निर्णय :-

दिनांक: 15.02.2022

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 29.09.2021 जो मिसल न० 179/21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम खारपाकलां की आराजी ख०न० 700 स्कवा 04 बीघा 15 बिस्वा किस्म बजड प्रथम में से 2 बीघा 08 बिस्वा पर अतिक्रमी मानकर 89/-रु० शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने उक्त बजड भूमि को अनुपजाऊ से उपजाऊ बनाया है एवं पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न० 556 दिनांक 05.10.2020 से 100 /-रु० शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पिडावा द्वारा अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्त द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्त का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है इसी क्रम में अपीलान्त उक्त आराजी पर भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेगा और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगा। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़